Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

कृषि में संतुलन

➢ हालिया संदर्भ :

- बजट 2025–26 पेश होने में अभी 45 दिनों से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है लेकिन बजट–पूर्व परामर्श एवं विभिन्न चर्चाएं जारी है।
- आगामी बजट में सर्वाधिक ध्यान कृषि क्षेत्र पर है।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी बजट में जो भी नीतियां एवं बजटीय आवंटन किया जाता है, उसका ध्येय कृषि को अधिक उत्पादक, प्रतिस्पर्धी, किसानों के लिए लाभकारी एवं पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल होने चाहिए।

➢ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव :

- भारत में उत्पादन प्रणाली प्रत्यक्षत: जलवायु परिवर्तन से प्रभावित रहा है।
- ** भारत में वर्ष 1951 की तुलना में तापमान में 0.7°C की वृद्धि हुई है जबकि बारिश (जुलाई–सितंबर) की मात्रा में 6% की गिरावट दर्ज की गई है।

- उपरोक्त स्थिति के कारण कृषि उत्पादन क्षेत्र के लिए जोखिम में वृद्धि हो रही है। अतः जलवायु–लचीली कृषि विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
- ** वर्तमान में कृषि–GDP (R&D) का 0.5% है, जिसे बढ़ाकर कम–से–कम 1% किए जाने की आवश्यकता है।

➢ जैविक खेती का मार्ग :

- मिट्टी में पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ एवं नमी तथा ह्यूमस (Humus) बनी रहे, इसके लिए कृषि पद्धति को भी बदलना जरूरी है।
- हाल में शुरू किए गए 'प्राकृतिक खेती मिशन' का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है लेकिन यह भारत की लगातार बढ़ती आबादी को भोजन सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो 2050 तक बढ़कर 167 करोड़ हो जाने का अनुमान है।
- चाहे वह जैव–उर्वरक हो या रासायनिक उर्वरक, मिट्टी में पर्याप्त उर्वरकता बनाए रखने के लिए संतुलित मात्रा में इनका प्रयोग आवश्यक है।
- ** नाइट्रोजन (N), फास्फेट (P) एवं पोटाश (K) जैसे Macro nutrients के साथ-साथ आयरन, जिंक, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषकों को सही संतुलन में प्रयोग में लाया जाना चाहिए।
- **Imp:–** Macro nutrients में उन पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है जिनकी आवश्यकता फसलों के तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। वहीं Micro–nutrients में उन पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है जिनकी आवश्यकता फसलों के तुलनात्मक रूप से कम होता है लेकिन दोनों ही फसलों के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।

➢ सही उर्वरक नीति :

- वर्तमान 'उर्वरक सब्सिडी नीति' उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा नहीं देती है क्योंकि अन्य पोषक तत्वों की तुलना में यूरिया पर ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, जिससे N का ज्यादा प्रयोग होता है जबकि P, K तथा अन्य Micro nutrients का कम प्रयोग होता है।
- इस सब्सिडी नीति के कारण नैनो–यूरिया, नैनो–DAP या सिंगल/ट्रिपल सुपर फास्फेट जैसे तकनीकी नवाचारों और उत्पादों की पहुंच सीमित है।
- अगर वर्तमान सरकार उपरोक्त कमियों को दूर कर सकती है (जो संभव होता दिख रहा है) तो यह भारत के किसानों के साथ-साथ देश की मिट्टी के लिए सकारात्मक परिणामों वाला होगा।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उर्वरक बिक्री एवं पीएम किसान जैसे योजनाओं के कारण सरकार के पास पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरित किया जा सकता है।
- ऐसा करने से उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, साथ ही पोषक तत्वों के उपयोग में संतुलन आएगा।

➢ सोच में बदलाव :

- *** वर्तमान में कृषि केवल खाद्य फसलों के उत्पादन की टोकरी नहीं है बल्कि इसे 'उत्पादन–विपणन–उपभोग' के खाद्य प्रणाली के रूप में माना जाना चाहिए। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों के आय में वृद्धि होगी।
- 'उत्पादन–विपणन–उपभोग' श्रृंखला बनाए जाने की शुरुआत फलों–सब्जियों से की जा सकती है ताकि उपभोक्ता द्वारा व्यय की राशि का 75–80% तक किसानों को प्राप्त हो सके।
- सहकारी समितियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की डेयरियों को अगर साथ ले लिया जाए तो श्वेत क्रांति–2.0 (दूध उत्पादन को बढ़ाना) को सफल बनाया जा सकता है, साथ ही चूंकि दूध का उत्पादन ज्यादातर छोटे किसानों द्वारा किया जाता है, इसलिए ऐसा वर्ग ज्यादा लाभान्वित होगा।
- *** भारत दूध के उत्पादन में 239 मिलियन टन के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है एवं USA 103 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है।

➢ प्रतिबंध, समाधान नहीं :

- प्याज, गेहूं, चीनी अथवा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर तथा FCI (भारतीय खाद्य निगम) द्वारा आर्थिक लागत से कम कीमत पर घरेलू बाजार में गेहूं या चावल की 'डंपिंग' कर सब्जी–मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना बेहतर विकल्प नहीं है।
- ध्यातव्य है कि FCI के लिए चावल की आर्थिक लागत 39 रुपए/kg है लेकिन यह घरेलू बाजार में 29 रुपए/kg की दर से चावल बिक्री कर रहा है जो किसान एवं बाजार विरोधी और यह उपभोक्ता समर्थक पूर्वाग्रह को दर्शाता है।

➢ उत्पादन समर्थन अनुमान (PSE) :

- *** दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों का PSE OECD यानि Organisation for Economic Co–Operation and Development द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके तहत विभिन्न कृषि नीतियों, बजटीय समर्थन एवं बाजार मूल्य समर्थन के प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है।
- *** 2023 में समाप्त होने वाले त्रैवार्षिक अवधि के लिए OECD देशों ने अपने कृषि को सकल कृषि प्राप्तियां में 13.8% का समर्थन दिया।
- *** दिलचस्प यह है कि चीन के लिए यह अनुपात जहां 14% है, वहीं भारत के लिए यह अनुपात –15.5 % यानि नकारात्मक में है।

➢ *** OECD :

- आर्थिक वृद्धि, समृद्धि एवं सतत विकास को बढ़ावा देने वाला एक संगठन है, जिसमें 38 देश सदस्य के रूप में शामिल है।
- इसकी स्थापना 1961 में हुई तथा इसका HQ पेरिस में है।
- भारत इसका सदस्य नहीं है।

➢ *** डंपिंग :

- यह एक ऐसी स्थिति है, जब कोई देश किसी उत्पाद को उसके घरेलू बाजार में कीमत से कम कीमत पर दूसरे देशों को निर्यात करती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति के लिए अनुचित माना जाता है।

MCQ –1 : निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें –

1. भारत में वर्ष 1991 की तुलना में तापमान में 1.7°C की वृद्धि दर्ज की गई है।
2. भारत में वर्ष 1951 की तुलना में बारिश (जुलाई–सितंबर) की मात्रा में कुछ कमी दर्ज की गई है।

a) केवल 1

b) केवल 2

c) न तो 1 न ही 2

d) 1 एवं 2 दोनों

Ans.–(b)

MCQ–2 : निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मैक्रो– न्यूट्रिएंट्स (Macro–nutrients) की सूची में सामान्यत: शामिल नहीं किया जाता है ?

a) नाइट्रोजन

b) आयरन

c) फास्फेट

d) पोटाश

Ans.–(b)

Result Mitra

Mains

Q–1 जलवायु–परिवर्तन के वर्तमान दौर में कृषि पर इसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। कृषि को सतत एवं उत्पादक–अनुकूल बनाए जाने के लिए उचित सुझाव दें।

Result Mitra